

>

Title: Need to enquire against Non-Government Organization (NGOs) supplying low quality material to Government Schools under Mi-day-meal Scheme.

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपसे मिड डे मील के बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ कि मिड डे मील सरकारी स्कूलों में शायद इसलिए लाया गया, ताकि गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ कुपोषण से भी बच सकें, लेकिन आज जो मिड डे मील एनजीओ या संस्थाओं के माध्यम से सप्लाई किया जाता है, वे इस पर पानी फेरने का काम कर रही हैं। आए दिन मिड डे मील से संबंधित शिकायतें आती हैं। कहीं पर मिड डे मील के खाने में छिपकली निकलती है, कहीं पर चूहा निकलता है, कहीं पर खाने में कांच निकलता है तो कहीं पर पानी जैसी दाल होती है। कहीं पर एक लीटर दूध में 84 बच्चों को पिलाने की बात होती है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार कुपोषण जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 'पोषण पखवाड़े' के माध्यम से लोगों को जागरूक करके कुपोषण से दूर करने का प्रयास कर रही है, वहीं ये संस्थाएं और एनजीओज हमारे इस कार्य पर पानी फेरने का काम कर रही हैं।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगी कि ऐसे मिड डे मील की संस्थाओं और एनजीओ, जिनको हम टेंडर देते हैं, उनकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल करके ही उनको टेंडर दिया जाए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार का सपना साकार हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. संघमित्रा मौर्या द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

